भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 297
मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025/11 अग्रहायण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

पीएसीएस को शामिल किए जाने के लिए कदम

297. श्री इमरान मसूदः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित कार्यों में कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से संबंधित प्राथमिक कार्यों को शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश की उक्त पहल का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने में क्या भूमिका है; और
(ग) उक्त पहल से विभिन्न गांवों में रहने वाले लोगों को किस प्रकार लाभ मिलना अपेक्षित है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में PACS की पहुंच का उपयोग करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति (PWS) के प्रचालन और रखरखाव (O&M) को करने के लिए PACS को पात्र एजेंसियों के रूप में बनाया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे ग्रामीण PWS के लिए प्रचालन और रखरखाव (O&M) एजेंसियों के रूप में PACS को शामिल करने के लिए अपनी प्रचालन और रखरखाव (O&M) नीति में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करें। साथ ही, इच्छुक PACS को प्रोत्साहित किया जाता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) द्वारा उनकी क्षमता निर्माण और कौशल सहित सहायता प्रदान की जाती है ।

इस पहल का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों के सहयोग पर निर्भर करता है। राज्यों को अपनी प्रचालन और रखरखाव (O&M) नीतियों में सक्षम प्रावधानों को शामिल करने और ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं में नियोजन हेतु उपयुक्त PACS को चिह्नित करने की आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश के मामले में, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन और रखरखाव को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी PACS को चिह्नित नहीं किया गया है । दिनांक 15.11.2025 तक, पंचायत/ग्राम स्तर पर O&M सेवाएं प्रदान करने के लिए 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा कुल 763 PACS को चिह्नित किया गया है । यह पहल न केवल PACS की आय में वृद्धि करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के संचालन के लिए एक मजबूत तंत्र भी प्रदान करेगी ।

*****